

संपादकीय पृष्ठ

पशुपालन क्षेत्र के लिए ऋण सुविधा में विस्तार

देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्वौपदी मुर्मू ने सोमवार को पद की शपथ ली और बतौर राष्ट्रपति पहली बार देश को संबोधित किया। उससे पहले निर्वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार शाम आखिरी बार देश को संबोधित किया। दिलचस्प है कि दोनों राष्ट्रपतियों ने अपने कार्यकाल के समापन और आरंभ के इस ऐतिहासिक मौके का इस्तेमाल करते हुए पर्यावरण के सवाल को महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित किया। चौदहवें राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि प्रथम नागरिक के रूप में अगर मुझे अपने देशवासियों को कोई एक सलाह देनी हो तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि प्रकृति माता गहरी तकलीफ में हैं और जलवायु संकट इस समूचे ग्रह के भविष्य को खतरे में डाल सकता है। इसी तरह नई राष्ट्रपति द्वौपदी मुर्मू ने कहा कि मेरा तो जन्म उस जनजातीय परंपरा में हुआ है जिसने हजारों वर्षों से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाया है। मैंने जंगल और जलाशयों के महत्व को अपने जीवन में महसूस किया है। हम प्रकृति से जरूरी संसाधन लेते हैं और उतनी ही श्रद्धा से प्रकृति की सेवा भी करते हैं। बेशक राष्ट्रपति हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख हैं और वह शासन के रोजमरा के कामकाज से ऊपर होते हैं। बावजूद इसके, अगर एक के बाद एक दोनों राष्ट्रपतियों ने इस मसले को अपने भाषण शामिल करने की जरूरत महसूस की तो यह अकारण नहीं हो सकता। पर्यावरण आज इतना बड़ा मसला होता जा रहा है जो हर मनुष्य के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है।

सरकारें अपने स्तर पर जो कुछ कर सकती हैं कर रही हैं, हालांकि वह जरूरत से बहुत कम है, लेकिन फिर भी उसमें इजाफा हो जाए तब भी वह काफी नहीं होगा। सरकारों की अपनी सीमा होती है। जरूरत इस बात की है कि हर व्यक्ति अपने सोचने-समझने, काम करने बल्कि कहें जीने के ढंग में बदलाव की न केवल तैयारी दिखाए बल्कि बदलाव सुनिश्चित करे। अपनी समझ बदलने और स्वेच्छा से खुद को बदलाव का वाहक बनाने से ही यह उद्देश्य पूरा हो सकता है। दोनों राष्ट्रपतियों ने अपने आखिरी और पहले भाषण के जरिए देशवासियों को यही संदेश देने की कोशिश की है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ सकती है। ध्यान रहे पिछले ही महीने विश्व बैंक की ओर से जारी की गई एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत सबसे निचली पांत के देशों में शामिल था। हालांकि इन एनवायरनमेंट रिपोर्टों के मानकों पर सवाल भी उठते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस सचाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि पर्यावरण संरक्षण के मामले में हम बहुत पीछे हैं और हमें बहुत कुछ करना है। बेहतर होगा कि नागरिक और सरकार दोनों इस मामले में तालमेल बनाए रखते हुए तेजी से आगे बढ़ें और दुनिया के सामने मिसाल पेश करें।

अतुल चतुर्वेद

2019 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक कार्य समूह ने उल्लेख किया था कि पारंपरिक कृषि कार्य में लगे किसानों के पास पशुधन और डेयरी किसानों की तुलना में ऋण प्राप्ति की बेहतर सुविधा मौजूद थी। चूंकि 75 प्रतिशत पशुपालक किसान 2-4 मवेशियों के साथ सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं, इसलिए भारत के पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों के लिए ऋण की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि संबद्ध गतिविधियों (पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन) को कुल कृषि ऋण का केवल 10 प्रतिशत प्राप्त होता है, जबकि वे कृषि उत्पादन में 40 प्रतिशत का योगदान देते हैं। पशुपालक किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती इस तथ्य से भी जुड़ी हुई है कि जनगणना के तहत एक किसान को उसकी जमीन के स्वामित्व/ज्ञोत के आधार पर परिभाषित किया जाता है। परिणामस्वरूप, पंजीकृत भूमि रिकॉर्ड के बिना किसानों के लिए ऋण प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। इस स्थिति के समाधान के लिए, सरकार ने पशुधन और डेयरी क्षेत्र में किसानों व उद्यमियों के लिए ऋण उपलब्धता एवं ऋण वित्तपोषण का विस्तार करने के उद्देश्य से कई उपाय पेश किये हैं।

सावजनिक और निजी क्षेत्र के बींकों द्वारा केवल 41 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान कवर किए गए हैं और बहुसंख्यक किसान सूदखोर साहूकारों के सामने असहाय हो जाते हैं। स्थिति में सुधार के लिए, पहला महत्वपूर्ण उपाय 2019 में सामने आया, जब किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा पशुधन क्षेत्र के किसानों को भी दी गई। केसीसी में बींकों को 2 प्रतिशत की ब्याज छूट

प्रदान की जाती है और किसानों को कृषि व संबद्ध गतिविधियों के लिए 3 लाख रुपये तक के अल्पावधि ऋण का समय पर भुगतान करने पर 3 प्रतिशत का प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे ऐसे ऋणों के लिए प्रभावी ब्याज दर कम होकर मात्र 4 प्रतिशत रह जाती है। केसीसी ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि लगभग 70 प्रतिशत पशुपालक महिलाएं हैं, जिनमें से अधिकांश को गिरवी योग्य सम्पत्ति के अभाव में ऋण प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

अधिक बर्बाद हो जाता है। इसके उपाय के लिए, देश भर में डेयरी सहकारी समितियों एवं किसान उत्पादक संघों को ऋण सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास योजना की घोषणा की गई थी। डीआईडीएफ अवसंरचना के विकास पर केंद्रित परियोजनाओं को प्रोत्साहन देकर देश में संपूर्ण डेयरी मूल्य श्रृंखला का उन्नयन करना चाहता है।

पिछले कुछ दशकों में, निजी क्षेत्र ने डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका

इसके अतिरिक्त, आरबीआई की रिपोर्ट में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि कुछ राज्यों को अपने कृषि-जीड़ीपी की तुलना में अधिक कृषि-ऋण प्राप्त होता है, जिसका अर्थ है कि कृषि ऋण का उपयोग गैर-कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। इस प्रकार यह क्षेत्रीय असमानता के मुद्दे को रेखांकित करता है, क्योंकि मध्य, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों को अपने कृषि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बहुत कम कृषि-ऋण प्राप्त होता है। इस संदर्भ में, सरकार ने कोविड लॉकडाउन के दौरान डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों के नेटवर्क का समर्थन करने के लिए कई उपाय प्रस्तुत किये, जिनमें प्रमुख हैं - कार्यशील पूँजी ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज छूट देने की योजना। इस योजना के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को 333 करोड़ रुपये जारी किए गए, ताकि इसकी मदद से 24,000 करोड़ रुपये के कार्यशील पूँजी ऋण को सहायता दी जा सके। इसके अलावा, डेयरी किसान बिजली की अनियमित आपूर्ति के कारण पैदा हुई चुनौतियों का सामना करते हैं। फलस्वरूप, कुल दूध उत्पादन का 3 प्रतिशत से निभाई गई है। वर्तमान में, लगभग 120-130 एमएमटी का प्रसंस्करण अवसंरचना अंतर है, जो लगभग 20,000 करोड़ रुपये की निवेश क्षमता को दर्शाता है। यदि दुग्ध प्रसंस्करण और वितरण के लिए अवसंरचना की जरूरतों को शामिल किया जाये, तो डेयरी मूल्य श्रृंखला में कुल संभावित निवेश अवसर 1,40,000 करोड़ रुपये का है। इसे ध्यान में रखते हुए, पशुपालन और डेयरी विभाग निजी कंपनियों व उद्यमियों के लिए पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ) के रूप में एक प्रमुख योजना लेकर आया है, ताकि डेयरी उत्पादों मांस उत्पाद और पशु चारा से संबंधित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए ऋण पर ब्याज छूट की सुविधा दी जा सके। क्रेडिट गारंटी जोखिम कम करने वाला एक महत्वपूर्ण उपाय है, जो एमएसएमई को ऋण देने के क्रम में ऋणदाता के जोखिम को कम करता है। इसलिए, 750 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी निधि की स्थापना की गई है, ताकि उधारकर्ता को उपलब्ध कराए गए मूल ऋण के 25 प्रतिशत तक के एएचआईडीएफ ऋणों के लिए गारंटीकृत कवरेज प्रदान किया जा

सके। मूल्य श्रृंखला में कमियों के दूर करने के लिए एएचआईडीएच को संबंधित किया गया है, ताकि योजना में नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी वैक्सीन निर्माण और कचरे से कंचन से संबंधित अवसंरचना निर्माण का शामिल किया जा सके।

हमारे पश्चुन क्षेत्र की कुप्रमुख चुनौतियाँ हैं - निम्न उत्पादकता स्तर और गुणवत्तापूर्वक किफायती पशु आहर तथा चाकी कमी। अतः इस क्षेत्र में किसान-

पुलिस प्रशिक्षण को महत्व देने का समय

विभूति नारायण राय

पिछले दिनों चौबीस घंटों के भीतर तीन अलग-अलग ओहदे के पुलिसकर्मियों की वाहनों से कुचलकर की गई हत्याओं को क्या महज संयोग माना जाना चाहिए? यह प्रश्न इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये हत्याएं देश के तीन राज्यों में हुईं, जिनमें अलग-अलग दलों या गठबंधन की सरकारें हैं। शायद यही कारण था कि इन पर कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं हुई, पर यह भी नहीं हुआ कि इन्हें लेकर विधायी सदनों या मीडिया में कोई गंभीर बहस हुई हो।

हरियाणा में नूह के निकट पुलिस उपाधीक्षक सुरेंद्र सिंह बिश्नोई, झारखण्ड की राजधानी रांची में महिला सब-इंस्पेक्टर संध्या टोपनो और गुजरात के आणंद जिले में कांस्टेबल किरण राज ड्यूटी के दौरान मारे गए। तीनों दुर्घटनाओं की परिस्थितियां एक जैसी ही थीं। तीनों में अपराधी तेज रफतार वाहनों में भागने की कोशिश कर रहे थे, तीनों में मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और तीनों ही जगह ड्राइविंग सीट पर बैठे दुस्साहसिक चालकों ने उन्हें कुचल दिया। एक बात स्पष्ट है, जाहिरा तौर पर इन घटनाओं में आपस में कोई संबंध न होते हुए भी समाजशास्त्र के किसी गंभीर विद्यार्थी को इनमें बड़े दिलचस्प अंतरसंबंध मिल सकते हैं।

सबसे पहले हमें पिछले सात दशकों में पुलिस और जन-सामान्य के रिश्तों में आए बदलाव को समझना होगा। आजादी के पहले पुलिस और जनता के बीच के रिश्ते कुछ वैसे ही थे, जिनकी किसी औपनिवेशिक समाज में अपेक्षा की जा सकती है। उन दिनों हिंदूभाषी इलाकों की लोककथाओं या लोकगीतों में एक मुहावरा जनता की जुबान पर चढ़ा हुआ मिलता है, जिसके अनुसार, गांव में खाकी पगड़ी दिखते ही पूरा गांव खाली हो जाता था और लोग आसपास के जंगलों में भाग जाते थे। बाद के कुछ दशकों तक इस स्थिति में कोई उल्लेखनीय बुनियादी फर्क नहीं पड़ा। स्वाभाविक था, एक नए बन रहे लोकतांत्रिक समाज में जनता बहुत दिनों तक पुलिस से अपने ऐसे रिश्ते नहीं स्वीकार कर सकती थी। परिवर्तन शुरू हुए, पर बहुत धीरे-धीरे। मैंने उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री को एलानिया कहते सुना है कि पुलिस का इकबाल तो उसकी हनक से कायम होता है। यह वही हनक है, जिसके चलते जनता गांव छोड़ जंगलों में भाग जाती थी। यह अलग बात है, लोकतंत्र के चलते सार्वजनिक

रूप से इस साच का समर्थन करने वाले कम हात गए हैं। इन दुर्घटनाओं के पीछे सबसे पहले हमें इसी मानसिकता को समझना होगा। हमारा औसत पुलिसकर्मी क्या अब भी यह नहीं सोचता कि उसके तन पर खाकी देखते ही अपराधी जड़ हो जाएगा और अपना वाहन बंद कर देगा? वह भूल जाता है कि अब यथार्थ बदल चुका है। वाहनों के इंजन ज्यादा ताकतवर हैं और उन्हें चलाने वाले व्यक्ति के मन से पुलिस का पारंपरिक खौफ खत्म हो चुका है। तीनों घटनाओं में अतिरिक्त आत्मविश्वास से लबरेज पुलिसकर्मी इसी भ्रम में मारे गए कि उनके इशारा करते ही वाहन रुक जाएंगे।

किसी वर्दीधारी संगठन में, जिसे हथियार दिए गए हैं, प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है। सेना में तो हर यूनिट की दीवार पर एक उत्तरांग लिंगवा दिखता है जिसका संदेश है कि प्रशिक्षण में जितना

पसीना बहाया जाएगा, युद्धक्षेत्र में उतना ही खून बचेगा। दुर्भाग्य से पुलिस में सबसे उपेक्षित क्षेत्र प्रशिक्षण ही है। ऊपर वर्णित तीनों घटनाओं का गहराई से अन्वेषण किया जाए, तो सिखलाई की कमियां बढ़ी स्पष्ट दिखेंगी और बिना सही सिखलाई के सशत्र बलों की कोई दुकड़ी किसी भी ढ़ से बेहतर नहीं होती।

पुलिस और कानून-व्यवस्था संविधान के अनुसार, राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है। राज्यों में अलग-अलग दलों

की सरकारें आती-जाती रही हैं, पर यह बिना अपवाद कहा जा सकता है कि किसी भी दल के लिए पुलिस प्रशिक्षण महत्वपूर्ण नहीं रहा है। अमूमन प्रशिक्षण केंद्रों पर बतौर सजा नियुक्तियां की जाती हैं और बिना रुचि वाले अधिकांश प्रशिक्षक अपने प्रशिक्षुओं को कितना पेशेवर बना पाते होंगे, इसकी कल्पना ही की जा सकती है।

लिए इसलिए भी आवश्यक है कि उसकी कोई भी कार्रवाई शून्य में नहीं होती।

हर क्रिया पर समूह के किसी अन्य सदस्य को भी हरकत करनी

होती है, इसीलिए एक एसओपी बनाई जाती है। हरियाणा के किसी भी जिले में अवैध खनन पर छापा मारने के पहले पुलिस कंट्रोल रूम या किसी उच्चाधिकारी को सूचित करना एसओपी का हिस्सा होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर आवश्यक बल भेजे जा सकें। जितनी जानकारियां सार्वजनिक हुई हैं, उनसे तो लगता नहीं कि इस जरूरी प्रक्रिया का पालन किया गया। खबरों के अनुसार, पुलिस उपाधीक्षक अवैध खनन की सूचना मिलते ही कुछ सहकर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। बिल्कुल ऐसे ही महिला सब इंस्पेक्टर ने पशु तस्करी के आरोपी ट्रक को अकेले दम पर रोकने का प्रयास किया। कांस्टेबल किरण ने ट्रक को क्यों रोकना चाहा, यह स्पष्ट नहीं है, पर उन्होंने भी पेशेवर अचरण का उल्लंघन किया। ममकिन है, समय की कमी या

परापर जावरण का उल्लंघन किया। मुमाकिन है, समय का कमा या गोपनीयता की वजह से इन पुलिसकर्मियों ने जरूरी सावधानियां न बरती हों, पर इतना तो प्रथम दृष्ट्या साफ है कि सामान्य सी एसओपी का पालन किसी में नहीं किया गया।

हमें थोड़े-थोड़े अंतराल पर पुलिसकर्मियों की ऐसी अस्वाभाविक मृत्यु की खबरें मिलती रहती हैं, पर एक छोटी सी अवधि में अलग-अलग प्रदेशों में तीन पुलिसकर्मियों की हत्या विचलित करने वाली है। ये घटनाएं पुलिस प्रशिक्षण की खामियों और पुलिस को बेहतर पेशेवर संस्था बनाने की जरूरत को रेखांकित करती हैं। अभी तक तो इन दुर्घटनाओं पर कोई गंभीर बहस होती दिख नहीं रही है। क्या नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्था पुलिस में घटी इतनी बड़ी दुर्घटनाओं में नागरिकों की इतनी कम दिलचस्पी चिताजनक नहीं है? या आम नागरिक पुलिस वालों की जिंदगी को इतना महत्व भी नहीं देते कि 24 घंटों के भीतर अकाल काल कवलित हुई तीन बेशकीमती जिंदगियों के लिए कुछ देर ठहरकर सोचें कि ऐसा क्यों कर हुआ और ऐसे उपाय करें कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो।

कट्टरपंथ व धर्मातरण

अवधेश कुमा

राष्ट्रीय जांच एजेंसी याने
एनआईए द्वारा बिहार के पटना-
फुलवारीशरीफ आतंकवादी मॉड्यूल
की जांच हाथ में लेने के साथ उसका
उम्मीद बंधी है। यानी पॉपुलर फ्रंट
ऑफ इंडिया, इससे जुड़े छोटे-बड़े
संगठनों की देश विरोधी गतिविधियाँ
का पूरा सच सामने आ जाएगा।
जितना सच अभी तक सामने आया
है वही हम सबको डराने के लिए
पर्याप्त है।

राज्य संरचना के वर्तमान ढांचों में ऐसे सभी मामलों में कानून-भूमिका होती है। बिहार पुलिस ने अभी तक की छानबीन में पाया है कि गजवा-ए-हिंद और बीआईपी ए पक्ष के जरिए देश विरोधी गतिविधियों में संलिप आरोपित मरणों अहमद दानिश उर्फ़ ताहिर नेपाल के कुछ मुस्लिम युवाओं से भी जुड़ा था। अलफलाही व्हाट्सएप ग्रुप से सब जुड़े थे और इस आजमगढ़ से ऑपरेट किया जा रहा था। भारत में अनेक आतंक गतिविधियों के सूत्र नेपाल से जुड़े पाए गए हैं। यह बात अलग है विनेपाल के आम लोगों से पूछें तो उनके लिए इस्लामी आतंकवाद या कट्टरवाद से ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां तथा धर्मार्तरण इस समय बड़ी समस्या मानी जा रही है। जैसा आप जानते हैं नेपाल पिछले काफी समय से राजनीतिक अस्थिरता की चपेट में था। वहां शेर बहादुर देउबा की सरकार है, जो भारत के साथ पूरी तरह तादात्मय बनाकर काम कर रही है। नेपाल में ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, जिनमानते हैं कि वहां की व्यवस्था और संविधान में संपूर्ण परिवर्तन ही सहृदायी और अंतिम उपाय है।

जानते हैं कि पिछले काफी समय से

वहां राजशाही को पुनः स्थापित करने तथा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए व्यापक पैमाने पर आंदोलन चल रहा है। नेपाल को हम किस तरह से देखते हैं यह हमारा आपका अपना दृष्टिकोण है किंतु वहां के लोगों में आंदोलन करने, सड़कों पर उत्तरने तथा स्वयं पहल करके परिवर्तन कराने का चरित्र भारत से कई गुना ज्यादा है। भारत में लंबे समय से इस्लामी कट्टरपंथ, आतंकवाद तथा ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां परेशानी के कारण बोरे दम हैं। ऐसा नहीं है कि लोग पुलिस-प्रशासन में इनकी गतिविधियों की शिकायत नहीं करते या सरकार तक बात नहीं पहुंची है। बावजूद वहां लोग अन्य सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक समस्याओं के साथ इसका हल यही मानते हैं कि नेपाल के संविधान को परिवर्तित किया जाए। उसमें सेक्युलर की जगह हिंदू राष्ट्र शब्द डाला जाए तथा वर्तमान संसदीय लोकतांत्रिक ढांचे को इस तरह परिवर्तित किया जाए, जिससे सर्वा जाता दोषी बोलता देजा जाए।

हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देने से किया इंकार



लखनऊ, 28 जुलाई (एजेसी)। हाईकोर्ट ने मई में सह-आरोपी अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी हिस्सा मामले में केंद्रीय गृह न्यायाधीश ने वहाँ बताया है। कोर्ट ने इसपर नियंत्रण करने के लिए केंद्र से कदम उठाने को कहा है। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली की बेंच ने केंद्र से कहा है कि इस समस्या का हल निकालने के लिए वित्त आयोग की सलाह का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने वहाँ बतायी की पालिप सिब्बल से भी इस मामले में राय मांगी। वह किसी और मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में मौजूद थे। सीजेआई ने कहा, प्रिस्टर सिब्बल यहाँ मौजूद हैं और वह एक वरिष्ठ संसद सदस्य भी है। आपका इस मामले में क्या विचार है? सिब्बल को कहा गया था कि वह एक कानूनी कोर्ट के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के विरोध स्थल पर पैदा हुई असांतिएक पूर्व नियोजित सामिजिश थी, न कि लापरवाही का परिणाम।

एसआईटी ने इस मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ करीब 5,000 पत्रों की चार्जीस्टी दाखिल की थी। इसने राज्य सरकार की आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने की भी सिफारिश की थी, जिसमें कहा गया था कि 'वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है और जमानत पर रहते हुए सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है।' हालांकि, राज्य सरकार ने जमानत को सुनीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी थी। पीड़ित उनकी जमानत याचिका पर परिवारों ने सुनीम कोर्ट में अपील पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।

लखनऊ बेंच ने इसी साल फरवरी में उन्हें जमानत दी थी।

हालांकि, सुनीम कोर्ट ने अप्रैल में जमानत के आदेश को रद्द कर दिया था और पीड़ित पक्ष को पर्याप्त अवसर देने के बाद हाईकोर्ट को उनकी जमानत याचिका पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।

खून दाग मिले और बिको को कुछ पता नहीं चला। आज सुबह गाड़ी से करीब 50 फीट नीचे जंगल में मैं उनका शव मिला। उसके चेहरे और गले में चोट के निशान थे। कालिम्पोंग पुलिस घटनास्थल पर जाकर जांच शुरू कर दी है। हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है। वहाँ का पोस्टमार्टम के लिए कालिम्पोंग जिला अस्पताल लाया गया है। वहाँ चालक की हत्या का चालक महासंघ ने कड़ी विरोध किया है और अपाराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।

कालिम्पोंग के दुःख

खून दाग मिले और बिको को कुछ पता नहीं चला। आज सुबह गाड़ी से करीब 50 फीट नीचे जंगल में मैं उनका शव मिला। उसके चेहरे और गले में चोट के निशान थे। कालिम्पोंग पुलिस घटनास्थल पर जाकर जांच शुरू कर दी है। हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है। वहाँ का पोस्टमार्टम के लिए कालिम्पोंग जिला अस्पताल लाया गया है। वहाँ चालक की हत्या का चालक महासंघ ने कड़ी विरोध किया है और अपाराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।

एसडीएफ से जल्द

हृष्णा और एसकेएम में शामिल होने के बाद भी मैं चौंजों की टीक करने की कोशिश करूंगा, मैं उन्हें एक वरिष्ठ जगतेज के तौर पर सलाह दूंगा और मुझे सीएम पर भरोसा है कि वह मेरे विचारों पर अपल करेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि एसडीएफ में मेरे योगदान के 30 साल हो गए हैं। मैं 30 साल तक हमारा समर्थन करने के लिए सिस्क्रिप्ट के लोगों की ध्यान देना चाहता हूँ। 2019 के चुनाव में हम हार गए, हमने विपक्ष के रूप में काम नहीं किया। पार्टी अध्यक्ष पवन चामलिंग ने भी पार्टी को आगे बढ़ाने की चिंता नहीं की, समन्वय की कमी के कारण मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। हमने जोर देकर कहा था कि हमें कोशिश करते रहनी चाहिए लेकिन हमें कोई जबाब नहीं मिला।

उन्होंने यहाँ तक कहा कि पवन चामलिंग कभी-कभी मुझे गुमशुदा उम्मीदवार कहकर ताना मारते थे। इसलिए मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं जल्द ही एसडीएफ पार्टी से इस्तीफा दे दूँगा और सही समय आने पर एसकेएम में शामिल हो जाऊंगा। जीएम गुरुंग एसडीएफ सरकार में चार बार मंत्री रहे हैं। जीएम गुरुंग एसडीएफ पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। 19 जुलाई को सीएम प्रेम रामतांग ने एसडीएफ पार्टी से इस्तीफा देने की अफवाह के बीच जीएम गुरुंग से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इससे अनुमान लगाया जा रहा था कि जीएम गुरुंग एसकेएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं।

एक दिवसीय कानूनी

इसके प्रबंधन पर बोलते हुए उपरिथित लोगों से इसके बारे में खुल कर चर्चा करने का आग्रह किया। उनके अलावा सदस्य सचिव श्रीमती यूसा लाचेन्या ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए इसके नियमित आयोजन की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण हेतु चलायी गयी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का भी आग्रह किया।

सिक्किम में फल-फूल

समाज के पक्ष में मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा खुले आम सचिवों एवं सरकारी कर्मचारियों को धमकाना उनके द्वारा अपने पद का अपमान करने के साथ ही गुणाराज का संकेत है। साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को खुले आम गुणाराज के उकसाना भी गुण्डा नेतृत्व का उदाहरण है। वास्तव में ऐसे लोग ही सिक्किम एवं यहाँ के अस्पत दुश्मन हैं। भूटाया के अनुसार कल पुलिस की सुरक्षा में हम बच गये। लेकिन आने वाले दिनों में हमारे जान-माल का कोई नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी यह आदेश देने वाले एसकेएम नेताओं एवं मुख्यमंत्री पीएस गोले पर होगी। उन्होंने सवाला किया कि क्या अब गृह्य में एसडीएफ के राजनीतिक कार्यकलापों के लिये पुलिस की सुरक्षा लेनी होगी?

चुनाव से पहले 'मुफ्तखोरी' पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, कहा- रेवड़ी कल्चर पर काबू करो

नई दिल्ली, 26 जुलाई (एजेसी)। चुनाव से पहले सुप्रीम योजनाओं का बाबा यानी 'रेवड़ी कल्चर' को सुप्रीम कोर्ट ने एक गंभीर मुद्दा बताया है। कोर्ट ने इसपर नियंत्रण करने के लिए केंद्र से कदम उठाने को कहा है। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली की बेंच ने केंद्र से कहा है कि वह इस समस्या का हल निकालने के लिए वित्त आयोग की सलाह का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने वहाँ बतायी की वकील कपिल सिब्बल से भी इस मामले में राय मांगी। वह किसी और मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में मौजूद थे।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि वकील कपिल



आयोग राज्यों को फंड आवंटित करता है तो उसे राज्य पर कर्ज और सुप्रीम योजनाओं पर विचार करना चाहिए।

सिब्बल ने कहा, वित्त आयोग ही इस समस्या से निपट सकता है। हम आयोग को इस मामले से निपटने के लिए कहा है कि वह इस समस्या का बहुत ही बड़ा काबू है।

सुनवाई के दौरान चुनाव

आयोग की तरफ से पेश हुए वकील

अमित शर्मा ने कहा कि पहले के

फैसले में कहा गया था कि केंद्र

सरकार इस मामले से निपटने के

लिए कदम उठाने से परहेज क्यों

कर रहा है।'

मामले में याचिकाकर्ता

आश्विनी उपाध्याय ने कहा कि यह

गंभीर मुद्दा है और पोल पैनल को

राज्यों और राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों

मिलता है।

पटना, 26 जुलाई (का.सं.)। सच्च वारंट मिलने के बाद आरोपी

बिहार में एक भ्रष्ट लोकसेवक पर

अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप

में निगरानी विभाग ने शिक्षित जास

दिया है।

पटना के शहरी विकास विभाग

के कार्यपालक अधियंता अनिल

कुमार यादव के ठिकानों पर विशेष

निगरानी की टीम छापेमारी कर रही

है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट

(एसडीयू) के पदाधिकारी आरोपी

इंजीनियर के आवास और कार्यालय

में बदल रहते हैं और आवास पर

ठेकेदारों को बुलाकर अवैध कर्माइ

करते हैं। तलात अनिल यादव पटना

के शहरी विकास एवं आवास

विभाग के कार्यपालक अधियंता के

पद पर तैनात हैं। स्पेशल विजिलेंस

यूनिट विशेष निगरानी न्यायाधीश के

गुप्त निवेश की आधार पर यह

પીએમ 28-29 જુલાઈ કો ગુજરાત, તમિલનાડુ કા કરેંગે દौરા

નई દિલ્હી, 28 જુલાઈ (એજેસી)। પ્રધાનમંત્રી નેંદ્ર મોદી

28-29 જુલાઈ કો ગુજરાત ઔર તમિલનાડુ કા દૌરા કરેંગે, ઇસ દૌરાન ઉનકા કઈ પરિયોજનાઓં કા ઉદ્ઘાટન ઔર શિલાન્યાસ ઔર કાર્યક્રમોં મેં ભાગ લેને કા કાર્યક્રમ હૈ।

વહ 28 જુલાઈ કો ગુજરાત કે સાબરકાંગ કે ગદોડા ચૌકી મેં સાબર ડેયરી કી કઈ પરિયોજનાઓં કા ઉદ્ઘાટન ઔર શિલાન્યાસ કરેંગે। ઇસે બાદ, પ્રધાનમંત્રી ચેત્રીં કી યાત્રા કરેંગે ઔર ચેત્રીં મેં 44વે શરતરં ઓલર્પિયાડ કી ઘોષણા કરેંગે।

અત્રા વિશ્વવિદ્યાલય કે 42વે દીક્ષાંત સમારોહ મેં ભાગ લેને કે બાદ, પ્રધાનમંત્રી ગુજરાત લૌટેંગે ઔર ગાધોગાર મેં ગાસ્ટ સિટી કા દૌરા કરેંગે, જહાં વહ વિભિન્ન પરિયોજનાઓં કા શુભાર્થ ઔર

આધારશાળ રહેંગે।

ગુજરાત મેં રહેણે હુએ વહ સાબર ડેયરી કા દૌરા કરેંગે ઔર 28 જુલાઈ કો 1,000 કરોડ રૂપે સે અધિક કી કઈ પરિયોજનાઓં કા ઉદ્ઘાટન ઔર શિલાન્યાસ કરેંગે।

પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય કે અનુસાર, 'યે પરિયોજનાએ સ્થાનીય કિસાનોં ઔર દૂધ ઉત્પાદકોં કો સશક્ત બનાએણી ઔર ઉનકી આય મેં વૃદ્ધિ કરેગી। ઇસસે ક્ષેત્ર કી ગ્રામીણ અર્થવ્યવસ્થા કો ભી બઢાવા પિલેંગા।'

પ્રધાનમંત્રી સાબર ડેયરી મેં લગભગ 120 મિલિન ટન પ્રતિદિન (એમ્ટિપીડી) કી ક્ષમતા વાલે પાઠડર લ્યાટ કા ઉદ્ઘાટન કરેંગે। પૂરી પરિયોજના કી કુલ લાગત 300 કરોડ રૂપે સે અધિક હૈ। વહ સાબર ડેયરી મેં તીન લાખ લીટર પ્રતિદિન કી ક્ષમતા વાલે એસેન્ટિક

મિલ્ક પૈકેજિંગ ખલાંટ કા ભી ઉદ્ઘાટન કરેંગે। ઇસ પરિયોજના કો લગભગ 125 કરોડ રૂપે કે કુલ નિવેશ કે સાથ ક્રિયાન્વિત કિયા ગયા હૈ।

વહ સાબર ચીન એંડ વ્હે ડ્રાઇંગ ખલાંટ પરિયોજના કી આધારશાળ ભી રહેંગે। પરિયોજના કા અનુમાનિત લાગત લગભગ 600 કરોડ રૂપે હૈ।

29 જુલાઈ કો, પ્રધાનમંત્રી

ગાંધીનગર મેં ગાસ્ટ સિટી (ગુજરાત ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનેસ ટેક-સિટી) કા દૌરા કરેંગે, જહાં વહ ભારત મેં અંતરરાષ્ટ્રીય વિત્તીય સેવા કેંદ્રોં મેં વિત્તીય ઉત્પાદન, વિત્તીય સેવાઓં ઔર વિત્તીય સંસ્થાનોં કે વિકાસ ઔર વિનિયમન કે લિએ એકીકૃત નિયમક, અંતરરાષ્ટ્રીય વિત્તીય સેવા કેંદ્ર પ્રાધિકરણ કે મુખ્યાલય ભનન કી આધારશાળ રહેંગે।

વહ ગિપ્ટ-આઈએસસી મેં ભારત કા પહુલા અંતરરાષ્ટ્રીય બલિયન એક્સચેન્જ ઇંડિયા ઇન્ટરનેશનલ બુલિયન એક્સચેન્જ (આઈઆઈબીએક્સ) ભી લોન્ચ કરેંગે। આઈઆઈબીએક્સ ભારત મેં સોને કે વિત્તીકરણ કો બઢાવા દેને કે અલાવા, જિમ્પેદાર સોસીસિંગ ઔર ગુણવત્તા કે આશ્વાસન કે સાથ કુશલ મૂલ્ય ખોજ કી સુવિધા પ્રદાન કરેંગે।

પ્રધાનમંત્રી ગાંધીનગર મેં ગાસ્ટ સિટી (ગુજરાત ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનેસ ટેક-સિટી) કા દૌરા કરેંગે, જહાં વહ ભારત મેં અંતરરાષ્ટ્રીય વિત્તીય સેવા કેંદ્રોં મેં વિત્તીય ઉત્પાદન, વિત્તીય સેવાઓં ઔર વિત્તીય સંસ્થાનોં કે વિકાસ ઔર વિનિયમન કે લિએ એકીકૃત નિયમક, અંતરરાષ્ટ્રીય વિત્તીય સેવા કેંદ્ર પ્રાધિકરણ કે મુખ્યાલય ભનન કી આધારશાળ રહેંગે।

29 જુલાઈ કો, ચેન્નાઈ મેં પ્રધાનમંત્રી ગાંધીનગર મેં ગાસ્ટ સિટી (ગુજરાત ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનેસ ટેક-સિટી) કા દૌરા કરેંગે, જહાં વહ ભારત મેં અંતરરાષ્ટ્રીય વિત્તીય સેવા કેંદ્રોં મેં વિત્તીય ઉત્પાદન, વિત્તીય સેવાઓં ઔર વિત્તીય સંસ્થાનોં કે વિકાસ ઔર વિનિયમન કે લિએ એકીકૃત નિયમક, અંતરરાષ્ટ્રીય વિત્તીય સેવા કેંદ્ર પ્રાધિકરણ કે મુખ્યાલય ભનન કી આધારશાળ રહેંગે।

ચેન્નાઈ કે જેએલેસન ઇંડોર સ્ટેડિયમ મેં આઈઆઈબીએક્સ કા સાત ઔર દ્વિતીં મુનેત્ર કષણમાં (ડિમુક) કે છહ સદસ્યોને સાહિત વિવિધ વિષાયી દલોનો કે કુલ 19 સદસ્યોનો મુંગલવાર કો ઇસ સાસાહ કી શેષ બૈઠકોને લિએ નિલંબિત કર દિયા ગયા।

રાજ્યસભા સે વિપક્ષ કે 19 સાંસદ નિલંબિત

નई દિલ્હી, 28 જુલાઈ (એજેસી)। સાંસદ કે માનુસનું સત્ર

કે દૌરાન સદન કે વેલ મેં પ્રવેશ કરને ઔર નારેબાજી કે લિએ રાજ્યસભા કે 19 સાંસદોનો મુંગલવાર કો ઇસ સાસાહ કી શેષ બૈઠકોને લિએ નિલંબિત કર દિયા ગયા।

રાજ્યસભા કી કાર્યવાહી મેં બાધા ડાલને ઔર વ્યવધાન ઉત્પન્ન કરને કે લિએ એટને તુંમળૂલ કાંગ્રેસ કે સાત ઔર દ્વિતીં મુનેત્ર કષણમાં (ડિમુક) કે છહ સદસ્યોને સાહિત વિવિધ વિષાયી દલોનો કે કુલ 19 સદસ્યોનો મુંગલવાર કો ઇસ સાસાહ કી શેષ બૈઠકોને લિએ નિલંબિત કર દિયા ગયા।

ગત 18 જુલાઈ સે આરંભ હુએ સંસદ કે માનુસનું સત્ર કે પહોલે દિન સે હી તમામ વિપક્ષી દલ મહાંગાઈ હુએ તુંમળાં હુએ સદસ્યોને સાહિત વિવિધ વિષાયી દલોનો કે કુલ 19 સદસ્યોનો મુંગલવાર કો ઇસ સાસાહ કી શેષ બૈઠકોને લિએ નિલંબિત કર દિયા ગયા।

નિલંબિત સદસ્યોનો મુંગલૂલ કાંગ્રેસ કે સાત, ડ્રિમુક કે છહ, તેલંગાના રાષ્ટ્ર સમિતિ (ટીઆરેસ) કે તીન, માર્કવાલી કાન્યુનિસ્ટ પાર્ટી (માકપા) કે દો ઔર ભારતીય કાન્યુનિસ્ટ પાર્ટી (ભાકપા) કે એક સંદર્ભ શામિલ હોયાં।

નિલંબિત સદસ્યોનો મુંગલૂલ કાંગ્રેસ કે સુખ્રિતા દેવ, માસમ નૂર, શાંતા છેત્રી, ડોલા સેન, શાંતનુ સેન, અંવીર રંજન વિશવાસ ઔર નારીમુલ ઇન્ક કો કાર્યવાહી બાર-બાર વાચિત હુએ ઔર અંતઃત: દિન ભર કે લિએ સ્થાગિત કર રહે હોયાં।

નિલંબિત સદસ્યોનો મુંગલૂલ કાંગ્રેસ કે સુખ્રિતા દેવ, માસમ નૂર, શાંતા છેત્રી, ડોલા સેન, શાંતનુ સેન, અંવીર રંજન વિશવાસ ઔર નારીમુલ ઇન્ક કો કાર્યવાહી બાર-બાર વાચિત હુએ ઔર અંતઃત: દિન ભર કે લિએ સ્થાગિત કર રહે હોયાં।

નિલંબિત સદસ્યોનો મુંગલૂલ કાંગ્રેસ કે સુખ્રિતા દેવ, માસમ નૂર, શાંતા છેત્રી, ડોલા સેન, શાંતનુ સેન, અંવીર રંજન વિશવાસ ઔર નારીમુલ ઇન્ક કો કાર્યવાહી બાર-બાર વાચિત હુએ ઔર અંતઃત: દિન ભર કે લિએ સ્થાગિત કર રહે હોયાં।

નિલંબિત સદસ્યોનો મુંગલૂલ કાંગ્રેસ કે સુખ્રિતા દેવ, માસમ નૂર, શાંતા છેત્રી, ડોલા સેન, શાંતનુ સેન, અંવીર રંજન વિશવાસ ઔર નારીમુલ ઇન્ક કો કાર્યવાહી બાર-બાર વાચિત હુએ ઔર અંતઃત: દિન ભર કે લિએ સ્થાગિત કર રહે હોયાં।